ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

लॉकडाउन में घर लौटे मजदूरों के कारण देश में धान का रकबा बढ़ा

रविवारीय, 09 - 15 अगस्त 2020 वर्ष - एक, अंक-53, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेंट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

मुख्यमंत्री ने कोझिकोड दुर्घटना पर दुख जताया

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने केरल के कोझिकोड में हुए विमान दुर्घटना पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा मेरी गहरी संवेदना पीड़ित परिजनों के प्रति है, उन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोया है। मैं हादसे में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। भगवान संकट की इस घड़ी में सभी को शक्ति दें।

कोरोना के कारण घुमंतू समुदाय पर सकट

लॉकडाउन ने पहले से बदहाल घुमंतू समुदाय की कमर तोड़कर रख दी है। पशुधन पर आश्रित ये समुदाय अब अपने पशुओं को खिलाने की स्थिति में नहीं है। राइका रैबारी समुदाय ने अपने ऊंटों को खुला छोड़ दिया है। भेड़-बकरी पालक भी हताश हैं। मार्च और अप्रैल में लगे लॉकडाउन ने इन घुमंतुओं को एक स्थान रुकने को मजबूर कर दिया जिससे इनकी सदियों से चली आ रही घूमने की परंपरा पर अचानक विराम लग गया। इस समुदाय पर किसी का ध्यान नहीं है।

यूरिया खाद की कीमत बढ़ कैसे जाती है? दूकानदार से लेकर होलसेलर, कृषि पदाधिकारी सभी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं आखिर

क्या है यूरिया का खेल ?

मुख्य संवाददाता

रांची : राज्य के किसानों को जब यूरिया खाद की बहुत ज्यादा आवश्यकता है तब इसकी कीमत वाजिब मूल्य से सौ रूपये तक बढ़ गयी है। झारखंड का किसान खुदरा दूकानदार से अस्सी से सौ रूपये तक ज्यादा कीमत देकर यूरिया खाद खरीद रहा है।

इस लॉकडाउन में जब वैसे ही सभी तंगी में जी रहे हैं वैसे में झारखंड का किसान ज्यादा कीमत देकर यूरिया खाद खरीद रहा है और वह विरोध भी नहीं कर रहा उसने हर साल की तरह बढी कीमत पर यूरिया खाद खरीदना अपनी नियति मान लिया है। किसान विरोध नहीं करता या खुदरा दूकानदारों से उसका विरोध प्रतीकात्मक भर होता है, वह जानता है कि उसके बोलने से कुछ नहीं होगा। उसे एक बोरा यूरिया खाद पर अस्सी से सौ रूपये अधिक देने ही देने हैं।

ऐसा भी नहीं है कि यूरिया की कीमत फसलों के लिये जरूरत के ऐन मौके पर या लॉकडाउन के बहाने पहली बार बढ़ी है। जिन्हें जानकारी है वह अच्छी तरह से जानते हैं कि हर साल आवश्यकता के समय यूरिया की कीमत में आग लग जाती है और किसी - किसी साल तो एक बोरा यूरिया प्राप्त करना छोटे किसानों के लिये किसी उपलब्धि के जैसा होता है। यहां सक्षम किसान बढ़ी कीमत पर भी यूरिया खरीद लेते हैं पर छोटे किसानों के लिये यह किसी शोषण से कम नहीं होता।

आखिर सरकारों और संबंधित विभागों के लाख दावे के बाद भी यूरिया के इस खेल पर अंकुश क्यों नहीं लग पाता? ग्रीन रिवोल्ट ने जब इस बारे में तहकीकात की और एक खुदरा दूकानदार ने जो बताया उससे यहीं आभास हुआ कि यूरिया खाद पर अधिक कीमत वसूलने में पूरा एक चेन है। जिसमें संबंधित अधिकारी से लेकर होलसेलर तक शामिल रहते हैं। यहां खुदरा दूकानदार तो सबसे नीचे के पायदान पर है। अधिकारियों का यह कहना कि उड़नदस्ता का गठन किया जा रहा है और गड़बड़ी करने वालों पर एक्शन लेंगे सिवाय एक प्रहसन के कुछ भी नहीं है। अगर वास्तव में एक्शन होता तो यूरिया की कीमत हर साल ऐसे ही नहीं बढ़ती।

क्या कहते हैं खुदरा दूकानदार ?

किसानों का सीधा सामना खुदरा दूकानदारों से होता है। किसान जब खुदरा दूकानदार से सौ डेढ सौ ज्यादा लेने का विरोध करते हैं तो दूकानदार उन्हें ऊपर से ही खरीद रेट महंगा होने की बात कहते हैं। और किसानों को मजबूरी में मन मसोस कर खुदरा दूकानदारों से महंगे दाम में यूरिया खाद खरीदना पड़ता है। जब ग्रीन रिवोल्ट ने रांची के ग्रामीण इलाके के एक खुदरा खाद विक्रेता से इसके बारे में जानकारी चाही तो उसका कहना था कि हमें ही होलसेलर अंकित मूल्य से ज्यादा कीमत वसूल कर खाद दे रहे हैं ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? जब ग्रीनरिवोल्ट संवाददाता ने होलसेलरों के बारे में और जानकारी चाही तो उसने आगे कुछ बताने से इनकार कर दिया।

यहां एक बात तो स्पष्ट हो गयी कि खुदरा दूकानदार खुद ऊंची कीमत पर होलसेलरों से यूरिया खरीद रहे हैं।

किसके कारण बढी यूरिया की कीमत?

खुदरा दूकानदरों के अनुसार होलसेलर की मनमानी के कारण ही प्रति बोरा सौ डेढ सौ तक खाद की कीमत बढ़ जाती है। और यह मनमानी होलसेलरों की है। इसके बाद हमने रांची में खाद के होलसेलरों के बारे में जब जानकारी एकत्र की तो हमें पता चला कि रांची में कृषि विभाग ने मुख्यत: तीन लोगों को खाद बेचने का लायसेंस दिया हुआ है। और यही तीनो होलसेलर जिले में खाद की कीमत और सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। इनमें से एक होलसेलर के करीबी से जब ग्रीन रिवोल्ट संवाददाता ने खाद की कीमत खुदरा दूकादारों से ज्यादा वसूलने की शिकायत की तो उसका कहना था कि हमें भी प्रति बोरा कुछ राशि रूपये कहीं देना होता है। उसकी भरपाई करनी होती है। ऐसे में कीमत तो बढ़ेगी ही।

अब ये जांच का विषय है कि होलसेलर सच हैं या झूठ? अगर उनकी बात सत्य है तो वह यूरिया के प्रति बोरे पर कुछ राशि किसे पहुंचा रहे हैं? जिसके कारण अंतत: गरीब किसानों की जेब कट रही है।

माननीया राज्यपाल महोदया ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जमशेदपुर निवासी श्री संदीप मुरारका द्वारा लिखित पुस्तक "शिखर को छूते ट्राइब्लस" का ऑनलाइन लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने विश्व आदिवासी दिवस 2020 के अवसर पर नीलाम्बर-पीताम्बर पार्क मोरहाबादी, रांची में पौधारोपण किया।

आदिवासी संस्कृति से हमें सीखनी चाहिये

मनोज शर्मा

सालों पहले एक बार मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ रांची से कुछ किमी दूर साइको नामक जगह पर पिकनिक के लिये गया था। वहां हम सभी नदी के किनारे भोजन कर रहे थे और बहते जल में बर्तन धोने से लेकर हाथ मुंह साफ कर रहे थे। वहां का एक स्थानीय युवक यह सब चुपचाप निराश भाव से देख रहा था। मेरे पूछने पर उसने मुझसे कहा कि इस नदी में हम लोग बगैर पूजा किये मछली भी नहीं मारते थे। लेकिन आज समय बदल गया है। आप लोग शहर से आते हैं और यहां मांस मछली बना कर इसी नदी में झूठे बर्तन से लेकर हाथ मुंह भी धोते हैं। जबकि यह नदी हमारे लिये पूजनीय है। उसकी इन बातों को सुन कर हम सभी शर्मिंदा हो गये।

9 जुलाई को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर समाचार पत्रों तक में इस पर कई तरह के लेख, पोस्ट, तस्वीरें देखने को मिलेंगे। इस दिवस के बारे में इतना कुछ और इस तरह से लिखा जायेगा कि यह दिवस भी अंतत: रस्मि सा महसूस होने लगेगा। हकीकत में तो इस दिवस को मनाने से ज्यादा हमें अपने आदिवासी भाइयों के रहन सहन उनके परंपराओं संस्कृतियों से कुछ सीखना चाहिये। आदिवासी समाज अब तक जल जल जमीन की रक्षा करते आ रहा है। वहां पहाड़ों से लेकर जंगलों, पेड़ों, जलक्षेत्रों को पूजने की परंपरा रही है। परंपरानुसार आवश्यकता से अधिक कभी भी किसी संसाधन का दोहन नहीं किया जाता। और तो और जलस्त्रोतों और कृषि भूमि को देवता का स्थान दिया जाता है।

मेरे मित्र संतोष उरांव ने बताया कि झारखंड की प्रमुख नदी दामोदर का वास्तविक नाम कुड़ख भाषा में दामोदह था वहां रांची के डोरंडा का वास्तविक नाम दुरंगदह (दो जलस्त्रोत)था । यहां दह का मतलब जल होता है। यह दोनो नाम ही अपभ्रंश होकर दामोदर और डोरंडा हो गये

आज शहरों में तालाबों, झीलों को प्रदूषित करने से लेकर उन्हें जमीन के लिये बर्बाद किया जा रहा है, पर आदिवासी समाज कभी किसी जलस्त्रोत को बर्बाद नहीं करता। वो किसी पेड़ को बस यूं ही नहीं काटते, वो पेड़ो की पूजा करते हैं। स्पष्ट है कि हमारा मूल आदिवासी समाज आधुनिक दौर में भी जल, जंगल, प्रकृति, पर्यावरण को लेकर पारंपरिक रूप से सजग है। हम भले आज विश्व आदिवासी दिवस मनायें अपने हीं भाइयों को संरक्षित की तरह प्रस्तुत करें, पर हकीकत में आदिवासी समाज शहरी सिविलाइज्ड लोगों से ज्यादा समर्पित और प्रकृति का रक्षक है।

ऊपरी खेतों में सरगुजा या कुल्थी की खेती करें कृषक

अजय कुमार

रांची केबिरसा कृषि विश्वविद्यालय की कृषि परामर्श सेवा ने प्रदेश के किसानों के लिए एग्रोमेट एडवाईजरी बुलेटिन जारी किया है। बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में पूरे राज्य में अच्छी वर्षा हुई है। अगले 2 - 3 दिनों में हल्की वर्षा या छिट -पुट वर्षा होने की संभावना है। प्रदेश के जो किसान धान को रोपा समाप्त नहीं कर पाये हों, उन्हें 2-3 दिनों में रोपा कार्य पूरा कर लेना उचित होगा।

बुलेटिन में बोआई से 15 - 20 दिनों वाली विभिन्न फसलों में मौसम को देखते हुए खर -पतवार नियंत्रण के लिए निकाई -गुडाई करने को कहा है। साथ ही जरूरत के मुताबिक यूरिया का भुरकाव करने का परामर्श दिया है।

विभिन्न फसलों पर भुआ-पिल्लु का आक्रमण दीखने एवं कम संख्या होने पर हाथ से चुनकर निदान करने को कहा गया है। ज्यादा संख्या होने पर भुआ-पिल्लु का आक्रमण दीखने पर कीटनाशी दवा डाइक्लोरभास (नुवान) का छि-ड़काव 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से साफ मौसम को देखते हुए करने को कहा गया है। इस दवा के घोल में टीपोल मिलाने या साबुन के पानी में तैयार करने का परामर्श दी गई है।

जल - जमाव से फसल क्षति से बचाव के लिए विभिन्न सब्जियों/फसलों के खेतों में जल निकास के लिए बनी नालियों को साफ एवं सुदृढ़ रखने को कहा है। जिन किसानों का ऊपरी खेत अभी भी परती रह गया हो, वे इस समय विभिन्न सब्जियों के आलावा कुल्थी या सरगुजा की खेती कर सकते है।

कुल्थी की खेती में इसकी उन्नत किस्म भीएलजी -19 या बिरसा कुल्थी में से किसी एक किस्म की बोआई की जा सकती है। एक एकड़ में बोआई के लिए 8 किलो बीज की आवश्यकता होती है। खेत तैयार करने के बाद बीज को हल के पीछे कतार में 30 सेंटीमीटर (कतार से कतार) तथा 10 सेंटीमीटर (पौधा से पौधा) की दूरी पर बोने तथा बीज को बोने से पहले राराइजोबियम कल्चर से उपचारित करने की सलाह दी गई है। सरगुजा की खेती में इसकी उन्नत किस्म बिरसा नाइजर -1, बिरसा नाइजर - 2, बिरसा नाइजर -3 या पूजा-1 में से किसी एक किस्म की बोआई करने को कहा गया है। एक एकड़ में बोआई के लिए 2 ।5 किलो ग्राम प्रति एकड़ बीज का प्रयोग करने, खेत तैयार करने के बाद बीज को हल के पीछे कतार में 30 सेंटीमीटर (कतार से कतार) तथा 15 सेंटीमीटर (पौधा से पौधा) की दूरी पर बोने को कहा है। छिड़काव विधि से बोआई में 3 ।5 किलो ग्राम प्रति एकड़ बीज का प्रयोग करने का परामर्श दिया है।

राज्यपाल ने लिखा :रउरे मनके जोहार! सोबेन को जोहार

राज्यपाल ने संदीप मुरारका की किताब ''**शिखर को छूते ट्राइबल्स**''के लोार्पण पर कहा कि आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें देती हूँ। मैं आज जमशेदपुर के लेखक संदीप मुरारका को उनकी कृति ''शिखर को छूते ट्राइबल्स'' की रचना हेतु अत्यन्त बधाई देती हूं और उनके उज्वल भविष्य की कामना करती हूँ।

आज लगभग सम्पूर्ण विश्व नोवेल कोरोना वायरस से जूझ रहा है। हमारा राष्ट्र भी इस भीषण चुनौती का सामना कर रहा है। मास्क के उपयोग के साथ ही सावधानी परहेज़ है। सुखद एवं गर्व का विषय है कि जहाँ हमारे राष्ट्र ने इस विपदा में दुनिया के मानवीय आधार पर लगभग 50 देशों को दवा भेजने का काम किया, वहीं हम वैक्सीन परीक्षण की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया ने हमारी मदद हेतु माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया है। संभवतः नोवेल कोरोना वायरस की परिस्थिति और हनपकमसपदम के कारण ही मैं ''शिखर को छूते ट्राइबल्स'' जैसे पुस्तक का लोकार्पण प्रत्यक्ष रूप से न कर, आप सभी दूर रह कर इस तकनीक के माध्यम से लोकार्पण कर रही हूं।

इस पुस्तक में जनजातीय समुदाय के 26 महान हस्तियों की जीवनियाँ हैं। इसके अन्तर्गत 18 वैसे महान विभूति हैं, जो पद्मश्री से अलंकृत हो चुके हैं। लेखक का यह अत्यन्त सराहनीय प्रयास एवं सोच है। इसके अतिरिक्त 8 और अन्य महान विभूतियों की जीवनियाँ समाहित हैं।कभी-कभी बहुत-से लोगों के मन में यह जिज्ञासा रहती है कि किन कारणों से ये महान विभूति पुरस्कृत हुए हैं। इन महान हस्तियों के क्या-क्या योगदान हैं? किन परिस्थितियों में इन्होंने संघर्ष किया? इस पुस्तक को लद्दाख में शहीद हुए भारत माँ के वीर सपूत गणेष हांसदा, नुदुराम सोरेन एवं राजेश ओरांग को समर्पित किया गया है।

प्लास्टिक एक भयावह वैश्विक पर्यावरणीय चुनौती बन चुका है

डॉ. कृष्ण कुमार मिश्र

आपने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में पीएच-डी. की उपाधि प्राप्त की। आप टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केन्द्र में एसोशिएट प्रोफेसर हैं। लोकप्रिय विज्ञान लेखक के रूप में आपकी अपार ख्याति है। आपके 300 से अधिक लेख तथा 24 पुस्तकें प्रकाशित हैं। के. एन. भाल नामित पुरस्कार, राजभाषा गौरव पुरस्कार, होमी जहाँगीर भाभा स्वर्ण पुरस्कार, विज्ञान परिषद् प्रयाग शताब्दी सम्मान, राजभाषा भूषण पुरस्कार सहित अनेक अलंकरणों से सम्मानित डॉ. मिश्र मुंबई में निवास करते हैं।

डॉ. कृष्ण कुमार मिश्र

प्लास्टिक, संश्लिष्ट या प्राकृतिक कार्बनिक यौगिकों के एक समूह को कहते हैं जिन्हें मुलायम होने पर वांछित शक्ल देकर बाद में सख्त बनाया जा सकता है। प्लास्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्लास्टिकोस से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है बनाना, निर्मित करना। प्लास्टिक का आविष्कार सन 1862 में इंग्लैंड के अलेक्जैंडर पार्केस ने किया था। महज डेढ़ सदी में ही प्लास्टिक पूरी दुनिया में छा गया। आज वह एक भयावह पर्यावरणीय संकट का रूप ले चुका है। पूरी दुनिया में प्लास्टिक का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। भारत में जहाँ हर व्यक्ति साल भर में औसतन 10 किलोग्राम प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है वहीं एक अमेरिकी 110 किलोग्राम प्लास्टिक का प्रयोग करता है।

दुनिया में हर साल करीब लाखों टन कूड़ा समुद्र में छोड़ दिया जाता है। इसमें अधिकांश प्लास्टिक होता है। ऐसा अनुमान है कि प्लास्टिक को स्वत: नष्ट होने में करीब 1000 साल लगता है। करीब 50 प्रतिशत प्लास्टिक हम केवल एक बार ही इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। प्लास्टिक इतना मजबूत होता है कि यह अपने भार का 2000 गुना वजन संभाल सकता है। इसकी इसी खूबी के कारण प्लास्टिक का इस्तेमाल दिनोंदिन बढ़ा है। ऐसा अनुमान है कि दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों की कुल खपत का करीब 8 प्रतिशत हिस्सा प्लास्टिक बनाने में खर्च हो जाता है।

प्लास्टिक ज्यादातर ओलिफींन्स (olefins) नामक पेट्रोरसायन से प्राप्त होता है। प्लास्टिक आम तौर पर उच्च आणविक भार के बहुलक यानी पॉलीमर होते हैं। इन पॉलीमर के विशाल अणु कार्बन परमाणुओं की बृहद् श्रृंखला पर, या कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला के साथ ऑक्सीजन, सल्फर, या नाइट्रोजन पर आधारित होते हैं। ये बड़े कण हैं जिन्हें पॉलीमर कहते हैं जो कि छोटे-छोटे कार्बनयुक्त इकाइयों के दुहराने से बनते हैं जिन्हें मोनोमर यानी एकलक कहते हैं। प्लास्टिक इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि इसकी लागत कम होती है तथा सस्ता होता है। इसे विभिन्न आकारों में सरलता से ढाला जा सकता है। प्लास्टिक का पैकेजिंग और घरेलू सामानों की व्यापक श्रृंखला में उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल यात्री विमान बनाने में भी किया जाता है। प्लास्टिक का प्रयोग वाहनों में भी किया जाता है। हम अपने आसपास दृष्टिपात करें तो सहज ही पाएंगे कि रोजमर्रा के हमारे जीवन में प्लास्टिक ने बहुप्रकारेण अन्यान्य रूपों में जबर्दश्त पैठ बना ली है। *जारी ....(इलेक्ट्रोनिकी आपके लिये से साभार)*

पहला मानव निर्मित प्लास्टिक ब्रिटिश रसायनज्ञ अलेक्जेंडर पाक्स द्वारा 1856 में बनाया गया था। उन्होंने इसे नाइट्रोसेल्यूलोज का उपयोग करके बनाया था। जिस कंपनी ने इस शुरुआती प्लास्टिक को बनाया था, वह बाद में दिवालिया हो गई।

आधुनिक प्लास्टिक युग का प्रादुर्भाव 1907 में बैकेलाइट के आविष्कार के साथ माना जाता है। बेल्जियमवासी अमेरिकी वैज्ञानिक लियो बैकलैण्ड द्वारा बैकेलाइट नामक संश्लेषित प्लास्टिक बनाया गया था। बैकलैंड ने फीनॉल को जीवाश्म ईंधन से प्राप्त पदार्थ को अपनी नई सामग्री बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। बैकेलाइट विद्युत का प्रतिरोधक तथा ऊष्मासह होता है। यह आसानी से वांछित आकार में ढाला जा सकता है। इसलिए यह विभिन्न चीजों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सन 1929 में पॉलीस्टाइरिन का आविष्कार किया गया।1930 में पॉलीस्टर, पॉलीविनाइलक्लोराइड(पीवीसी) तथा वर्ष 1933 में पॉलिथीन और 1935 में नायलॉन का आविष्कार हुआ। वर्ष 1941 में पॉलीइथाइलीन टेरिथैलेट (पीईटी) का आविष्कार हुआ। यह प्लास्टिक आमतौर पर सोडा की बोतल के लिए उपयोग किया जाता है। इस तरह समय के साथ तरह तरह की गुणवत्ता वाले नवीन प्लास्टिकों का आविष्कार हुआ।

बंद खदानों में एसिडिक पानी की वजह से मछलियों की जान को खतरा

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 5 अगस्त, 2020 के आदेश में कहा कि मध्य प्रदेश के जिला सिंगरौली के विंध्य नगर की खदान में जमा एसिडिक पानी की निगरानी की जानी चाहिए।

यह आदेश मछली पालन सहकारी समिति के अध्यक्ष सुभाष कुशवाहा द्वारा अदालत में दायर उस याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया, जिसमें कहा गया था कि विंध्य नगर के गोरबी कोयला खदान में फ्लाई ऐश का अवैज्ञानिक तरीके से निपटान वहां के निवासियों के मछली पकड़ने को प्रभावित कर रहा है।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में ट्रिब्यूनल को सूचित किया गया कि वर्तमान में मैसर्स नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) सिंगरौली कोयला खदान को बहुत पहले बंद कर दिया गया है, इसलिए यह एक निष्क्रिय खदान है।

ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

हादसे का इंतजार

हाल ही में बेरूत में एक गोदाम में रखे अमोनियम नाइट्रेट के जखीरे में दुर्घटनावश विस्फोट हो गया और बेरूत शहर बर्बाद हो गया। सैकड़ों जानें जा चुकी हैं, हजारो घायल है। इंटरनेट पर इस भयंकर हादसे का वीडियो देख कर इसकी भयावहता का हम अंदाजा लगा सकते है। सैकड़ो किमी तक इसकी आवाज सुनी गयी।

राज्यों में एक मुख्य कारखाना नीरीक्षक का पद होता है । जिसका मुख्य काम कारखानों में दुर्घटना रोकने के लिये सारे उपायों, मानदंडो को चेक करना होता है, समय समय पर उपकरणों की जांच करना और खतरनाक हो चुके उपकरणों, निर्माणों को हटवाना और दुरूस्त करवाना उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन प्रायः ये अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाते।

पिछले साल मूरी के हिंडाल्को फैक्ट्री में कचड़े का तालाब क्षमता से अधिक गाद के एकत्र होने पर मेड़ तोड़ कर बह निकला और फैक्ट्री का गाद खेतों में फैल गया। इस कारण से कृषि योग्य भूमि भी बर्बाद हो गयी। गाद का बहाव रेलवे ट्रैक के करीब तक हो गया था, पर संयोग से आवागमन बाधित नहीं हुआ।

इस हादसे के बाद भारत में भी चेन्नई में अमोनियम नाइट्रेट के जखीरे को वहां से स्थानांतरित करने की मांग हो रही है।

चेन्नई जैसे घनी आबादी वाले महानगर में एक जगह पर इतनी मात्रा में विस्फोटक पदार्थों को रखना ही बेवकूफी है। कल्पना किजिये भारत जैसे देश में किसी आतंकी संगठन को बड़ी वारदात देने के लिये किसी विस्फोटक की क्यों जरूरत होगी?

भारत में कारखानों में छोटी मोदी दुर्घटनायें हमेंशा होती ही रहती हैं और हमसे इससे कोई सबक नहीं लेते। हम किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार करते हैं , कुछ दिनों तक चाक चौबंद रहते हैं और फिर सारे नियम कानून ताक पर रख देते हैं।कारखानों में या खतरनाक विस्फोटकों के रखरखाव में लापरवाही और उससे जुड़ी दुर्घटनाओं में भारत अग्रणी है। हम आज तक भोपाल गैस त्रासदी का जख्म झेल रहे हैं। हाल के कुछ महिनों में आंध्र प्रदेश से लेकर देश भर के कारखानों में एकाएक दुर्घटनाओं की बाढ़ सी आ गयी है। बेरूत विस्फोट के बाद हमारे यहां चेन्नई में भी एक जगह पर रखे गये टनों अमोनियम नाइट्रेट को हटाने की बात तो हो रही है, लेकिन मूल सवाल है कि भारत में सबक लेने के लिये किसी हादसे का इंतजार क्यों होता है? हम पहले से ही सतर्क क्यों नहीं रहते?

बेरूत विस्फोट पर :साभार कार्टून मूवमेंट

सीपीआरआई ने ईजाद की रोग रहित पहाड़ी आलू की नई किस्म, भंडारण क्षमता भी ज्यादा

आलू पर लगने वाले पिछेता झुलसा और निमोटोड सहित अन्य वायरसों से जो किसान परेशान रहते हैं, उनको अब घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) के वैज्ञानिकों ने आलू की नई किस्म कुफरी करण विकसित की है। हिमाचल सहित देश के पहाड़ी और पठारों में इस किस्म की बेहतर पैदावार हो सकती है और इसकी भंडारण क्षमता भी ज्यादा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई बीमारियों और वायरस से लड़ने की क्षमता आलू की इस नई किस्म कुफरी करण में मौजूद है।

आलू की फसल सबसे ज्यादा पिछेता झुलसा रोग से प्रभावित होती है। इसके अलावा आलू की फसल को जो छह वायरस तबाह करते हैं, उनसे भी यह किस्म लड़ सकती है। इस आलू का इस्तेमाल सब्जी बनाने में किया जा सकेगा। कुफरी करण के इस सफेद आलू के बीच के कंदों का भार 40 से 60 ग्राम तक होता है। देश के ऊंचाई वाले इलाकों में यह आलू अप्रैल-मई और मध्य पहाड़ों में जनवरी-फरवरी में उगाया जा सकता है। पठारों में इसकी पूरा साल फसल होगी। यह आलू 10 से 12 सेंटीमीटर गहराई में उगाना होगा। साढ़े तीन से चार टन प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत पड़ती है। इस किस्म से 25 .1 टन प्रति हेक्टेयर आलू की पैदावार ले सकेंगे। फसल तैयार होते ही आलू निकालने में विलंब न करें। आलू के भंडारण से पहले आलू की खराब कंदों को नष्ट कर दें।

करीब 120 दिन में तैयार होती है फसल

सीपीआरआई के फसल सुधार विभाग के प्रमुख डॉ. विनय भारद्वाज कहते हैं कि कुफरी करण आलू बीमारी और निमोटोड जैसे वायरसों से लड़ने की क्षमता रखता है। भोज्य आलू की पैदावार भी अच्छी है और यह 100 से 120 दिन में तैयार हो जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार का अतिरंजित प्रचार

एस महेंद्र देव

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन महत्त्वपूर्ण है क्योंकि देश की आबादी और श्रम शक्ति का करीब 70 प्रतिशत गांवों में ही रहता है। इनकी क्रय शक्ति में इजाफा पूरी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग सुधारने के लिहाज से अहम है। इस संदर्भ में हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति का परीक्षण किया और देखा कि उसमें नई जान फूंकने के लिए किन उपायों की आवश्यकता है जो समूची अर्थव्यवस्था के लिए मददगार साबित हों।

कोविड-19 महामारी ने ग्रामीण भारत को अपेक्षाकृत कम प्रभावित किया है। ऐसी खबरें भी हैं कि लॉकडाउन के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेहतरी आ रही है। यह सही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार अब काफी हद तक कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार पर निर्भर है। वित्त वर्ष 2021 में कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 से 3 फीसदी की दर से विकसित होने का अनुमान है जबकि समूची अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद 5 से 8 फीसदी तक घट सकता है। मॉनसून के सामान्य रहने के कारण खरीफ और रबी दोनों मौसमों में शानदार फसल होने का अनुमान है। बहरहाल, इसके कारण उपज की कीमतों में कमी भी आ सकती है। इतना ही नहीं आपूर्ति शृंखला की दिक्कतों के कारण संभव है कि किसानों को फसल का उचित मूल्य भी न मिले। कृषि क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कहानी का केवल एक हिस्सा है। बीते समय में गैर कृषि आय और रोजगार भी बढ़ते रहे हैं।

नाबार्ड के एक सर्वेक्षण के मुताबिक ग्रामीण परिवारों की केवल 23 फीसदी आय ही खेती से आती है। नीति आयोग के एक अध्ययन के मुताबिक राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था 46 फीसदी की हिस्सेदार है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि ग्रामीण आय का दो तिहाई अब गैर कृषि गतिविधियों से उपजता है। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति रिपोर्ट में भी कहा गया, कोविड-19 के पहले के समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था दबाव में थी क्योंकि कारोबारी शर्तें कृषि के प्रतिकूल हो गई थीं और ग्रामीण वेतन भत्तों में बढ़ोतरी कम हुई थी क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र में मंदी थी। कोविड-19 ने पहले से संकटग्रस्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रभावित किया है।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर जो मार्च में 8.4 फीसदी थी वह अप्रैल में 22.9 फीसदी, मई में 22.5 फीसदी और जून में 10.5 फीसदी रही। दूसरे शब्दों में लाखों ग्रामीण श्रमिकों का रोजगार चला गया। केंद्र, राज्य सरकारों और आरबीआई ने इन चुनौतियों को पहचाना और कई उपायों की घोषणा की। केंद्र सरकार के पैकेज में खाद्यान्न हस्तांतरण, नकद हस्तांतरण, मनरेगा फंड में इजाफा, पीएम किसान योजना की राशि का आवंटन, कृषि क्षेत्र में सुधार आदि शामिल हैं। परंतु ये उपाय शायद धनप्रेषण में आई कमी तथा ग्रामीण मेहनताने में घटोतरी की भरपाई न कर सकें। बुरी बात यह है कि महामारी का प्रसार अब छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी होने लगा है। जून और जुलाई में ग्रामीण क्षेत्रो में सुधार ने शहरी क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया। दैनिक उपयोग की उपभोक्ता वस्तुओं के अलावा दोपहिया वाहनों और ट्रैक्टरों की मांग में सुधार के रूप में यह नजर भी आया। बहरहाल, ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुधार लॉकडाउन के बाद मांग बढने से आया था। यह कोई स्थायी सुधार नहीं था क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के वेतन भत्तों में कमी है और आय भी घट रही है। ऐसे में शायद घोषित राजकोषीय उपाय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए पर्याप्त न हों। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले किसानों की आय बढ़ानी होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा जरूरी है लेकिन आपूर्ति श्रृंखला को सुधार कर ही फसल के अच्छे दाम मिल सकते हैं। अनिवार्य जिंस अधिनियम, कृषि विपणन और अनुबंधित कृषि से संबंधित कृषि सुधार की मदद से मध्यम अवधि में आय में सुधार किया जा सकता है। बहरहाल, सरकार को इन सुधारों पर और अधिक स्पष्टता लानी होगी, इसमें केंद्र-राज्य समन्वय भी शामिल है। इसी प्रकार कृषि निर्यात को भी बढ़ावा देना होगा और निर्यात नीति पर काम करना होगा। दूसरा, राहत उपायों का विस्तार करके प्रवासी श्रमिकों को इसमें शामिल करना होगा।

जून में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि करीब 8 करोड़ से अधिक लोगों को पांच महीने और यानी नवंबर के आखिर तक निःशुल्क राशन दिया जाएगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई इसके दायरे से छूट न जाए। इसी प्रकार नकद हस्तांतरण की राशि और मनरेगा के तहत काम के दिन भी बढ़ाने होंगे। आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन और मैंने सुझाव दिया था कि कोविड के बाद के दौर में कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी आय तय की जाए। इसके लिए एकबारगी राजकोषीय गुंजाइश बनानी होगी। मध्यम अवधि में हम दोबारा राजकोषीय स्थिरता की ओर लौट सकते हैं। तीसरी बात, हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बुनियादी क्षेत्र में निवेश की आवश्यकता है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से रोजगार और वेतन बढ़ाए जा सकते हैं। हमें कृषि से परे जाकर गोदाम, लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण और खुदरा क्षेत्र में निवेश करना होगा। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में होने वाला विनिर्माण भी रोजगार और वेतन भत्तों में वृद्धि के लिए अहम है। सन 2004-05 और 2011-12 के दरमियान विनिर्माण ने ग्रामीण श्रमिकों के मेहनताने में इजाफे में अहम भूमिका निभाई। चौथा, करीब 51 फीसदी सूक्ष्म लघु और मझोले उपक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। उनमें भी नई जान फूंकनी होगी। कोविड-19 ने इन्हें बड़ा झटका दिया है। यह क्षेत्र पहले ही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संकट से जूझ रहा था। बिना इस क्षेत्र के आत्मनिर्भर बनना संभव नहीं है। कृषि और गैर कृषि लिंकेज, ग्रामीण-शहरी संपर्क भी ग्रामीण स्थिति में सुधार की दृष्टि से अहम हैं। प्रोफेसर टीएन श्रीनिवासन के अनुसार श्रमिकों को गैर कृषि कार्यों में लगाना इसका एक हल है। शहरी प्रोत्साहन पैकेज जो बैलेंस शीट और कारोबारी तथा बैंकिंग क्षेत्र की दिक्कतों को हल करेगा वह ग्रामीण भारत के लिए भी मददगार होगा क्योंकि दोनों के बीच संबंध है।

सरकार का राहत पैकेज और बढिया फसल से मांग और आय में सुधार होगा लेकिन यह कमजोर धनप्रेषण, रोजगार और वेतन भत्तों में कमी का मुकाबला नहीं कर सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार के लिए ऐसे उपाय अपनाने होंगे जिससे किसानों की आय में सुधार हो, आपूर्ति श्रृंखला बेहतर हो, श्रमिकों को राहत मिले, एमएसएमई में सुधार और और ग्रामीण-शहरी संपर्क बेहतर हो। इससे सारी अर्थव्यवस्था में मांग बेहतर होगी क्योंकि आबादी के बड़े हिस्से की क्रय शक्ति सुधरेगी और खपत भी बेहतर होगी।

(लेखक आईजीआईडीआर, मुंबई के निदेशक एवं कुलपति हैं)

आज के कोविड रिकवरी विकल्प कल का पर्यावरण निर्धारित कर सकते हैं

निशांत सक्सेना

कोविड से हुई आर्थिक हानि की भरपाई की योजना में जलवायु सम्बन्धी नीतिगत कदमों को अगर जोड़ा जाए और हरियाली का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया जाए तो हम मौजूदा नीतियों के तहत वर्ष 2050 तक अनुमानित ग्लोबल वार्मिंग में आधी से ज्यादा की कमी ला सकते हैं। लॉकडाउन के कारण लगे आर्थिक झटके से उबरने की कार्ययोजना में अगर जलवायु के प्रति अनुकूल विकल्पों पर ज़ोर देकर उन्हें जोड़ा जाए तो इससे ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जंग में खासी मदद मिल सकती है। इस बात की जानकारी नेचर क्लाइमेट चेंज पत्रिका में आज जारी एक ताजा अध्ययन से मिलती है।

गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान ग्रीनहाउस गैसों तथा हवा प्रदूषित करने वाले तत्वों के उत्सर्जन में अचानक गिरावट होने के बावजूद इसका वैश्विक तापमान पर इस्का कोई खास असर नहीं पड़ा है। अनुसंधानकर्ताओं ने आगाह किया है कि लॉकडाउन जैसे कुछ कदमों का सिलसिला वर्ष 2021 के अंत तक भी जारी रह सकता है, लेकिन अगर सुगठित उपाय नहीं अपनाये गये तो वर्ष 2030 तक अपेक्षित स्तर के मुकाबले वैश्विक तापमान में महज 0.01 डिग्री सेल्सियस की ही गिरावट आयेगी।

हालांकि लीड्स यूनिवर्सिटी की अगुवाई में किये गये अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि आर्थिक भरपाई की योजना में जलवायु सम्बन्धी नीतिगत कदमों को जोड़ा जाए और हरियाली का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया जाए तो हम मौजूदा नीतियों के तहत वर्ष 2050 तक अनुमानित ग्लोबल वार्मिंग में आधी से ज्यादा की कमी ला सकते हैं। इससे वैश्विक तापमानों को पैरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान में बढ़ोत्तरी को डेढ़ डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का अच्छा मौका मिलेगा। साथ ही इससे जोखिमों के साथ - साथ उच्च तापमान के कारण होने वाले गम्भीर दुष्परिणामों को भी टाला जा सकेगा।

पियर्स फॉस्टर और उनकी बेटी हारिएट ने हिसाब लगाया कि फरवरी से जून 2020 के बीच 123 देशों में 10 विभिन्न ग्रीनहाउस गैसों और वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन में कैसे बदलाव आया। उनकी टीम ने इस बात को विस्तार से बताया है कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर हुए बदलावों और औद्योगिक गतिविधियों पर विराम लगने के कारण वैश्विक स्तर पर सीओ2, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा अन्य प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन में 10-30 प्रतिशत तक की गिरावट के बावजूद जलवायु पर इसका बेहद मामूली असर पड़ेगा। ऐसा इसलिये क्योंकि उत्सर्जन में आयी यह कमी स्थायी नहीं है। शोधकर्ताओं ने लॉकडाउन के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिये विकल्प भी सुझाये हैं। इनमें दिखाया गया है कि मौजूदा हालात हमारे सामने सुगठित आर्थिक बदलावों को लागू करने का अनूठा अवसर दे रहे हैं, जो हमें अधिक सतत और पूरी तरह से प्रदूषणमुक्त भविष्य की तरफ बढ़ने में मदद कर सकते हैं। अध्ययन में कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले वाहनों, सार्वजनिक परिवहन और साइकिल लेन को प्रोत्साहित कर यातायात से होने वाले प्रदूषण को कम करने के अवसरों को भी रेखांकित किया गया है। अगर हवा की गुणवत्ता अच्छी होगी तो उससे सेहत पर महत्वपूर्ण प्रभाव फौरन पड़ेंगे और इससे जलवायु तुरंत ही ठंडी होना शुरू हो जाएगी।

हारिएट फॉस्टर ने कहा हमारे अध्ययन से जाहिर होता है कि लॉकडाउन से जलवायु पर दरअसल बहुत मामूली सा असर पड़ा है। अहम बात यह है कि इसके जरिये हमें प्रदूषणमुक्त कारखाने लगाकर अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का बेहतरीन अवसर मिला है। इससे भविष्य की जलवायु में बहुत बड़ा अंतर पैदा किया जा सकता है। इस अध्ययन के सह-लेखक क्यूरीन लू कुएरी ने कहा के अगर सरकारें लॉक-डाउन के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिये उठाये जाने वाले कदमों में जलवायु का ख्याल रखने पर भी ध्यान दें तो इससे जलवायु परिवर्तन के गम्भीर दुष्परिणामों को टालने में मदद मिल सकती है। प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन में जो भारी गिरावट आयी है उसका वर्ष 2030 तक वैश्विक तापमान पर कोई मापने योग्य असर नहीं होगा। मगर इस संकट से उबरने के रास्तों को लेकर इस साल लिया गया फैसला हमें पैरिस समझौते को निभाने के लिये ठोस मार्ग उपलब्ध करायेगा।''

मैथ्यू गिडेन ने कहा "कोविड-19 के कारण जलवायु पर पड़ने वाला असर कितने लंबे वक्त तक रहेगा, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि इस संकट के दौरान क्या हुआ, बल्कि इस पर निर्भर करेगा कि संकट खत्म होने के बाद क्या होगा। जलवायु को बेहतर बनाने की अपनी प्रतिज्ञाओं को अमलीजामा पहनाने के रास्ते पर दुनिया को लाते वक्त नुकसान की प्रदूषणमुक्त भरपाई और कम कार्बन उत्सर्जन वाले उपायों में निवेश पर ध्यान दिए जाने से अर्थव्यवस्था को नई शुरुआत मिल सकती है।

नासा जीएसएफसी में स्थित ग्लोबल मॉडलिंग एंड एसिमिलेशन ऑफिस में गोडार्ड अर्थ साइंसेज, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च के क्रिस्टोफर केलर ने कहा "कोविड-19 महामारी के कारण इंसानी गतिविधियों में आई कमी ने हमें वातावरणीय वायु प्रदूषण पर इंसानी प्रभाव को बेहतर तरीके से नापने का एक अनोखा अवसर दिया है।

टमाटर किसानों की चांदी

कुल्लू में फलों के बेहतर दाम मिलने के बाद सब्जियों को भी व्यापारी हाथों हाथ ले रहे हैं। कुल्लू का टमाटर स्थानीय मंडियों में 35 से 40 रुपये किलो बिक रहा है। सेब उचित दाम में बिकने के साथ ही टमाटर के दाम मिलने से घाटी के किसानों के चेहरे खिल गए हैं। इससे पहले फूलगोभी, गोभी और मटर में किसानों को काफी घाटा उठाना पड़ा था। पिछले साल सीजन के दौरान टमाटर पांच से दस रुपये किलो तक बिका था। इस बार किसानों को टमाटर के दाम तीन गुना अधिक मिल रहे हैं। किसानों को उम्मीद जगी है कि पिछले साल के नुकसान की भरपाई इस साल हो जाएगी।

इस वर्ष घाटी के किसानों के साथ युवाओं ने भी टमाटर उत्पादन के व्यवसाय को अपनाया है। कोरोना काल में युवाओं का फसलों की ओर रुझान बढ़ा है। सब्जी मंडियों में टमाटर का एक क्रेट 750 से 800 रुपये तक बिका। किसानों ने कहा कि सब्जी मंडियों में बरसात के मौसम में हर वर्ष टमाटर के दामों में गिरावट आती है। इस वर्ष फसल के जो दाम अभी मिल रहे हैं। इसकी उम्मीद किसानों को नहीं थी। टमाटर के 35 से 40 रुपये किलो दाम मिलने से किसान खुश है। कुल्लू और स्नोर वैली आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष खुशहाल ठाकुर ने कहा कि पिछले वर्ष घाटी में टमाटर की बंपर फसल के बावजूद मांग न होने से किसानों को दाम नहीं मिल पाए थे। इस वर्ष फसल कम होने की वजह से किसानों को टमाटर के अच्छे दाम मिल रहे हैं।

नोनूरोनल कोशिकाओं के संक्रमण से कोरोना रोगियों के सूंघने की क्षमता घटती है

निष्कर्ष बताते हैं कि कोविड-19 रोगियों में सूंघने की क्षमता के लिए विभिन्न प्रकार की नोनूरोनल कोशिकाओं का संक्रमण जिम्मेदार हो सकता है कोविड-19 के अधिकांश मरीजों के उभरते आंकड़ों के अनुसार मरीज सूंघने में कुछ स्तर तक परेशानी का अनुभव करते हैं, जो अक्सर अस्थायी होते हैं। कोविड-19 के रोगियों में 27 बार सूंघने की क्षमता में कमी होती है। कुछ अध्ययनों से पता चला कि कोविड-19 में सूंघने की क्षमता का नुकसान अन्य वायरल संक्रमणों के कारण एनोस्मिया से भिन्न होता है, कोविड-19 के रोगी में आमतौर पर हफ्तों के दौरान सूंघने की क्षमता ठीक जाती हैं । महीनों की तुलना में वह बहुत तेजी से सूंघने की क्षमता से उबर सकता है, जो वायरल संक्रमण के सबसेट के कारण होता है, जो घ्राण संवेदी न्यूरॉन्स को सीधे नुकसान पहुंचाता है।

कोविड ने बढ़ाया बुंदेलखंड में तुलसी, गिलोय और औषधीय पौधों की खेती

मुरलीधर

कोविड प्रकोप के बाद जिस तेजी से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय जैसे औषधीय पौधों का इस्तेमाल शुरू हुआ है, उसका असर इनकी खेती पर भी देखने को मिल रहा है। बुंदेलखंड, खास तौर से झांसी में तुलसी की खेती करने वाले किसानों के साथ ही रकबे में भी इजाफा हुआ है। तुलसी के साथ ही यहां मेंथी, एलोवेरा जैसी औषधीय महत्व के पौधे भी बड़ी मात्रा में उगाए जा रहे हैं। इनको बड़ी कंपनियां सीधे किसानों से अच्छी कीमत पर खरीद रही हैं।

पिछले करीब छह माह से पूरा देश कोविड महामारी की चपेट में है। इस दौरान प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर खास जोर दिया जा रहा है। आयुर्वेद में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा आदि को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला माना गया है। इस वजह से बाजार में इनकी मांग भी बढ़ी है। पिछले वर्ष ब्लॉक बंगरा, मऊरानीपुर, गौराठा में 400 किसानों ने तुलसी रोपी थी लेकिन अबकी बार इनकी संख्या बढ़ गई। उद्यान अधीक्षक भैरम सिंह के मुताबिक इस बार किसानों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले वर्ष करीब 600 हेक्टेयर में तुलसी लगाई गई थी लेकिन, इस बार यह रकबा करीब बीस फीसदी बढ़ गया। बाहर की कई कंपनियां भी अपने स्तर पर इनका उत्पादन करा रही हैं। तुलसी की श्यामा एवं रामा प्रजाति की मांग सबसे अधिक है। तीन माह में इसकी फसल तैयार हो जाती है। इन दिनों जुलाई-सितंबर के बीच फसल लगाई गई है।

बुंदेलखंड में रामा प्रजाति की तुलसी की बोवाई अधिक हो रही। तुलसी का पत्ता समेत बीज, जड़, तना काफी उपयोगी होता है, इसलिए व्यवसायी किसानों को पूरे पौधे का दाम देते हैं। लागत के मुकाबले फायदा अधिक होने से किसान भी तुलसी लगाने में दिलचस्पी दिखाते हैं। अन्ना जानवर भी इस पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते, इस वजह से इनकी देखभाल की भी अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी तरह अश्वगंधा, एलोवेरा एवं गिलोय का भी पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन बढ़ गया है। इसी तरह मोंठ, चिरगांव में किसान पिपरमेंट अथवा मेंथा का भी व्यापक पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं।

बुंदेलखंड में तुलसी एवं एलोवेरा के लिए किसानों की मदद की जाती है। उद्यान अधीक्षक भैरम सिंह के मुताबिक तुलसी उत्पादन के लिए किसानों को 13278 रुपये प्रति हेक्टेयर जबकि एलोवेरा के लिए 18 हजार रुपये की मदद की जाती है। उत्पादन के बाद कई कंपनियां किसानों से सीधे उत्पाद खरीदतीं हैं।

जैविक तुलसी पर अधिक जोर

महामारी के चलते तुलसी की बोवाई कंपनियों की ओर से भी अधिक कराई गई है। झांसी में कुछ जाने-माने ब्रांड की कंपनियां किसानों से सीधा संपर्क करके बोवाई कराती हैं।

किसानों को कंपनियां ही बीज आदि उपलब्ध कराती हैं। किसानों का कहना है कि कंपनियों की ओर से जैविक तुलसी की मांग काफी अधिक बढ़ गई है। खेत में किसी प्रकार की खाद नहीं डाली जाती। तुलसी लगाने वाले किसानों को करीब 40 हजार रुपये प्रति एकड़ तक की कमाई हो जाती है।औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बबीना ब्लॉक के सरबो गांव को मॉडल गांव के तौर पर बनाया जा रहा। यहां किसानों को सिर्फ औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा। उद्यान विभाग की योजना के मुताबिक अधिक उत्पादन के बाद कंपनियों को सीधा किसान सीधा अपना उत्पाद बेचकर अधिक आय हासिल कर सकेगा। झांसी स्थित आयुर्वेद कंपनी ने इसके लिए अपनी दिलचस्पी दिखाई है।

क्या झारखंड जहां औषधीय पौधों की खेती की बहुत संभावनायें हैं वो भी इस दिशा में बढेगा?

निगरानी करना भी है जरुरी: एनजीटी

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 31 जुलाई, 2020 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए एक आदेश जारी किया है इस आदेश में यह निर्देश दिया गया है कि वह अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाऐ मामला पर्यावरण मंजूरी और उसकी निगरानी से जुड़ा है कोर्ट ने इस निर्देश में मंत्रालय से सतत विकास और जनता के भरोसे से जुड़े सिद्धांतों को ध्यान में रखने की सलाह दी है

पूरा मामला पर्यावरण संरक्षण (अधिनियम), 1986 के तहत पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की शर्तों के अनुपालन से जुड़ा है जिसके प्रभावी निगरानी तंत्र के लिए उठाए जाने वाले कदमों को 14 सितंबर, 2006 में एक अधिसूचना के जरिए स्पष्ट किया गया थो कोर्ट ने कहा है किसी भी प्रोजेक्ट के एसेस्समेंट के आधार पर पर्यावरण मंजूरी के लिए केवल शर्तें तय करना ही काफी नहीं है जब तक की उसके पूरा हो जाने तक उसकी निगरानी नहीं की जाती और जब तक उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता तब तक मंत्रालय की जिम्मेदारी बनी रहती है।

मंजूरी के बिना हानिकारक रसायन निर्माण में लगा था मेसर्स ओम रसायन

हरियाणा में द स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट एस्सेसमेंट अथॉरिटी (एसईआईएए) ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तुरंत फॉर्मलडीहाइड के निर्माण पर रोक लगाने के लिए कहा है मामला हरियाणा के यमुनानगर की तहसील बिलासपुर के कुराली गांव का है जहां मेसर्स ओम रसायन फॉर्मलडीहाइड नामक इस खतरनाक रसायन के निर्माण में लगा हुआ था। इस मामले में एस-ईआईएए ने एनजीटी में अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, जिसके अनुसार इस यूनिट ने इस काम के लिए पर्यावरण मंजूरी नहीं ली है।

चिखली में नदियों को प्रदूषित होने से रोकेगा एसटीपी

पुणे :पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम (पीसीएमसी) द्वारा एनजीटी के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत गई थी जिसमें चिखली (12 एमएलडी), बोफेल (5 एमएलडी) और पिंपल निलख (15 एमएलडी) में 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के महत्व को समझाया गया था।

रिपोर्ट में पीसीएमसी-पुणे क्षेत्र के अंदर तीन प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थानों का उल्लेख किया गया है। पीसीएमसी क्षेत्र के अंदर एसटीपी के निर्माण को शुरू करने की अनुमति मांगी गई है। पीसीएमसी की सीमा में तीन नदियां बह रही हैं - मुला, इंद्रायणी और पवना। चिखली और अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में नाले सीधे इंद्रायणी नदी में मिल रहे हैं। अनुपचारित पानी का कुछ हिस्सा इंद्रायणी नदी के किनारे, अलंदी तक बहता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि चिखली में एसटीपी का निर्माण करना बेहद आवश्यक है, जो अनुपचारित पानी को उपचारित करेगा और इसे इंद्रायणी नदी में मिलने से रोकेगा। पीसीएमसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चिखली में एसटीपी का निर्माण 'कानूनी और उचित' है और किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। एसटीपी का निर्माण नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित नहीं करेगा क्योंकि नदी के उच्च बाढ़ स्तर (एचएफएल) को देखते हुए योजना बनाई गई थी। एसटीपी के निर्माण से नदी के क्रॉस सेक्शन में भी बदलाव नहीं होगा।

कोयले की आत्मनिर्भर योजना के खिलाफ चार राज्यों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी

एजेंसियां

केंद्र की कोयले की आत्मनिर्भर योजना के खिलाफ चार राज्यों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, आदिवासी नेताओं ने भी आशियाना छिनने का विरोध किया है। देश में कोयले की खदानों पर सरकार का नियंत्रण रहा है लेकिन इन नए 40 कोलफील्ड के आवंटन में निजीकरण को तरजीह दी जा सकती है।

कोल ब्लॉक आवंटन के खिलाफ चार राज्यों के सीएम ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। अपनी महत्वकांक्षी 'आत्मनिर्भर भारत' योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कोयले के आयात को कम करने की योजना बनायी है। इसके लिए सरकार ने देश में ही 40 नए कोल फील्ड (कोयले की खदान) खोलने का फैसला किया है।

गौरतलब है कि ये कोल फील्ड जिन जंगलों में खोले जाएंगे, उनमें से कई भारत के जैव विविधता वाले संवेदनशील जंगल हैं, जिनके तबाह होने से पर्यावरण को भारी नुकसान होने की आशंका है। जिन कोलफील्ड को खोलने की अनुमति दी जाएगी, उनमें से 4 बड़े ब्लॉक छत्तीसगढ़ के हसदेओ अरंड नामक जंगल में हैं। 4,20,000 एकड़ भूमि में फैले इस हसदेओ अरंड जंगल से करीब 5 बिलियन टन कोयला निकलने की उम्मीद है। देश में कोयले की खदानों पर सरकार का नियंत्रण रहा है लेकिन इन नए 40 कोलफील्ड के आवंटन में निजीकरण को तरजीह दी जा सकती है। बता दें कि इन कोल फील्ड के लिए जो कंपनियां बोली लगा रही हैं, उनमें अडाणी ग्रुप आदि शामिल हैं। हालांकि इन कोल फील्ड की नीलामी पर विवाद शुरू हो गया है।

दरअसल इन 40 कोल फील्ड में से 7 कोल फील्ड ऐसे हैं, जिनमें कोयले की खुदाई पर रोक थी क्योंकि ये जंगल पर्यावरण के लिहाज से काफी अहम हैं और साथ ही 80 फीसदी कोल ब्लॉक आदिवासी लोगों के घर हैं। यही वजह है कि चार राज्यों की सरकारों पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कोल ब्लॉक की नीलामी पर आपत्ति जतायी है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, एक स्थानीय आदिवासी उमेश्वर सिंह अमरा का कहना है कि कोल ब्लॉक की नीलामी ना हो इसके लिए वह अपनी जान भी देने को तैयार हैं। अमरा ने कहा कि साल 2011 में जंगल के बाहरी इलाके में कोयला खनन की मंजूरी दी गई थी। जिसके बाद यह इलाका प्रदूषण, गर्मी और शोर से भर गया है। यहां अपराध की दर तेजी से बढ़ी है ,जंगल में रहने वाले हाथी उग्र हो गए हैं, जिनके हमले में कई लोगों की जान जा चुकी है। अमरा ने कहा कि कोयला खनन के चलते उनके इलाके में पांच गांव तबाह हो चुके हैं और छह हजार आदिवासी विस्थापित हो चुके हैं और हजारों हेक्टेयर भूमि से पेड़ काटकर सड़कें और खदान बनायी जा रही हैं।

धान को फफूंदी से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा दवा का करें छिड़काव

एजेंसियां

बरसात के मौसम में धान की फसल को विभिन्न प्रकार के कीटों से बचाने के लिए कृषि बीज भंडार कार्यालय ने आवश्यक उपाय बताए हैं। इससे कीट लगने की आशंका से किसानों को मुक्ति मिल सकती है। कीटों और रोगों से बचाकर किसान अच्छा पैदावार ले सकते हैं।

किसानों का भरपूर देखभाल ही धान की फसल का सबसे अच्छा प्रबंधन है। बारिश के मौसम में धान की फसल में विभिन्न प्रकार के कीट लग जाते हैं, जिससे फसल को नुकसान होता है। धान की फसल में खरपतवार अधिक हो तो उसकी निराई और गुड़ाई के साथ ही कीटनाशक दवा को प्रति एकड़ के हिसाब से सौ लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इस मौसम में धान की फसल में दीमक लग सकता है। इसका सबसे अधिक प्रकोप असिंचित क्षेत्र में होता है। यह कीट पौधों की जड़ काट देता है और धीरे धीरे पौधा सूख जाता है। बाद में वह आसानी से उखड़ जाता है। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोपायरीफास 20 ई सी 4 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें।

धान की फसल में जीवाणु झुलसा रोग भी लग सकता है। इसके लगने से पत्तियों की नोक व किनारे सूख जाते हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए खेत का पानी निकालकर 15 ग्राम स्टप्टोसाइक्लीन व कॉपर आक्सीक्लोराइड का 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। धान की फसल में फफूंदी लगे तो एक किलोग्राम ट्राइकोडर्मा दवा प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं। जो कि कृषि रक्षा इकाई पर 100 रुपये प्रति किलो में उपलब्ध है। इस पर 75 प्रतिशत अनुदान भी उपलब्ध है।

एनजीटी ने बिहार सरकार को लगाई फटकार

न्यायमूर्ति एस पी वांगड़ी ने बिहार सरकार को उसके 'उदासीन और अस्वीकार्य' रवैये के लिए फटकार लगाई है।

मामला बिहार के मुंगेर जिले का है जहां महानॉय नदी के तट पर अवैध निर्माण किया जा रहा थो इस मामले में महानॉय रिवर सेफ्टी सोसाइटी ने कोर्ट के समक्ष एक अर्जी दाखिल की थी जिसके अनुसार महानॉय नदी में जिस तरह से गन्दा पानी डाला जा रहा है उसने इस नदी को एक नाले में बदल दिया है कोर्ट ने इस मामले में बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला मजिस्ट्रेट, मुंगेर से इस मामले की जांच करने और उसके बारे में रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि इससे पहले ट्रिब्यूनल ने 18 फ-रवरी, 2019 को एक आदेश जारी किया थो जिसमें कहा था कि मामले में निर्धारण के लिए सबसे पहले प्रश्न यह है कि मुंगेर जिले के टेटिया बम्बर में बीडीओ के ब्लॉक और आंचल कार्यालय का निर्माण नदी की सीमा के भीतर किया गया था या नहीं। इसके अलावा, क्या राज्य सरकार द्वारा नदी के किनारों पर निर्माण के लिए कोई नियम या मानदंड निर्धारित किए थे।

26 अगस्त, 2019 को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार अदालत के समक्ष ऐसे किसी भी नियम को सामने रखने में विफल रही थी। हालांकि एनजीटी के अनुसार बिहार बिल्डिंग बाय-लॉ, 2014 के नियम 22 (2) के तहत इस बारे में कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं जिसके अनुसार निर्माण नदी के 100 मीटर के दायरे में किया गया है जो निषिद्ध क्षेत्र है

राज्य द्वारा फिर से समय मांगा गया और मामले कई बार कोर्ट में आया है और उसे स्थगित करना पड़ा है। ऐसे में एनजीटी ने 31 जुलाई को एक आदेश जारी किया है जिसमे राज्य सरकार को 15 सितंबर से पहले अपनी रिपोर्ट सबमिट करने का अंतिम अवसर दिया है।

कोरोनावायरस को बढ़ने से रोकते हैं प्रोटीज एंजाइम अवरोधक

नए अध्ययन से पता चला है कि कैसे छोटे अणु प्रोटीज को रोकने से लोगों में फैलने वाले कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ा जा सकता हैं। प्रोटीज एक एंजाइम है जो प्रोटीन और पेप्टाइड्स को तोड़ता है। युनजॉन्ग किम और कायोंग-ओके 'केसी' चांग, अमेरिका की कैनसस स्टेट यूनिवर्सिटी में पशु चिकित्सा कॉलेज में वायरस वैज्ञानिक (वायरोलॉजिस्ट) हैं। उन्होंने एक अध्ययन किया है जिसमें कोविड-19 के संभावित चिकित्सीय उपचार के बारे में बताया गया है। अध्ययन अध्ययन में कहा गया है 3सी जैसे प्रोटीज एंजाइम अवरोधक (इनहिबिटर) विट्रो में कोरोनावायरस को बढ़ने से रोक देते हैं। इससे अध्ययन में उपयोग किए गए चूहों के मॉडल, मर्स-सीओवी से संक्रमित चूहों के जीवित रहने में सुधार होता हैं।

कर्मचारियों को मंडल रेल प्रबंधक ने पुरस्कृत किया

रांची : 6 जुलाई को मंडल रेल प्रबंधक नीरज अम्बष्ठ ने अपने कक्ष में लॉकडाउन अवधि में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए कार्मिक विभाग के 20 रेल कर्मियों को प्रशस्ति पत्र एवं नगद राशि देकर पुरस्कृत किया।

कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया था इस परिस्थिति में जरूरतमंद लोंगो को राँची रेल मंडल द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था। कोरोना वायरस के संक्रमण के भय के बाद भी राँची रेल मंडल के कार्मिक विभाग के अधिकारी तथा कमर्चारियों द्वारा स्वेच्छा से दिनांक 31.03.2020 से 10.05.2020 तक प्रतिदिन अलग - अलग स्थानों पर जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित किया।

श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आने वाले यात्रियों को सर्वो राँची मंडल की ओर से उपलब्ध कराये गए जीवन आवश्यक सामग्री को वितरित किया । साथ ही मंडल के वाणिज्य विभाग, रेल सुरक्षा बल, आई आर सी टी सी एवं भारत स्काउट एंड गाइड के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया तथा मदद की।

उपरोक्त सभी कार्य करने के लिए कार्मिक विभाग के कर्मचारी उदय कुमार, हेम लाल लकड़ा, एमपी गुप्ता, राजन कुमार, जितेंद्र चौधरी, असीम राय, ओंकार सिंह, हरेंद्र कुमार, रवि तिर्की,संजय कुमार चौरसिया, दीपक कुमार, मनोज कुमार झा, सुनील उरांव,मुकेश कुमार, रवि राजा, अनुपम भारती, श्रीमती सुधा सुमन बाखला, दिनेश राय, श्रीमती नीता मुंडू तथा जितेंद्र लोहरा को पुरस्कृत किए गए इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सह मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नीरज कुमार एवं वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी माणिक शंकर उपस्थित थे ।

मटर की खेती में कम अवधि वाली धान किस्मों की खेती फायदेमंद

संवाददाता

रांची : प्रदेश में वर्षा आधारित खेती पर निर्भरता और सीमित सिंचाई के कारण बहुतायत किसान रबी फसलों की खेती नहीं कर पाते है। बीएयू अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), चतरा द्वारा लोचदार कृषि तकनीकी के बढ़ावा ने किसानों की सोच को बदल दिया है।

चतरा जिला मुख्यालय से 7 किलो मीटर की दूरी पर स्थित निकरा अंगीकृत मरदनपुर गांव के किसान सिंचाई के आभाव एकफसली धान की खेती मात्र किया करते थे। कम आमदनी से किसानों में खेती की कम अभिरुचि के कारण रोजी- रोजगार के लिए बाहर पलायन करते थे। गांव में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के तहत पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार तथा नये तालाबों के निर्माण से जल संचय की सुविधा विकसित किये जाने से कृषि योग्य सिंचित भूमि 7 प्रतिशत से बढ़कर 45 प्रतिशत तक हो गई। 120 जनजातीय किसान परिवार वाले इस गांव के किसान लंबी अवधि वाली धान किस्म एमटीयू 1010 तथा 175 दिनों वाली स्थानीय किस्म जो -160 की खेती की वजह से दिसम्बर अंतिम सप्ताह में धान की कटाई के बाद दूसरी फसल नहीं ले पाते थे।

किसानों की परेशानी को देख केवीके वैज्ञानिकों ने गांव के 42 आदिवासी किसानों की कुल 17 हेक्टेयर भूमि में सबसे पहले कम अवधि (90-110 दिनों) वाली धान किस्मों अंजलि, वंदना, सहभागी और अभिषेक का अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण (एफएलडी) कराया गया। नवम्बर के प्रथम सप्ताह में धान की कटाई के बाद खेतों में 30-40 प्रतिशत नमी की

उपलब्धता पाया गया। इस नमी के उपयोग से सभी 42 आदिवासी किसानों के खेतों में संतुलित मात्रा में उर्वरको के प्रयोग तथा कीट व्याधि प्रबंधन से मटर (प्रभेद आरकेल) की खेती को एफएलडी माध्यम से बढ़ावा दिया गया। इस खेती से किसानों को औसत उपज 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से करीब 1 लाख 12 हजार 9 सौ रूपये कुल आमदनी मिला।

केवीके, चतरा के प्रभारी डॉ. रंजय कुमार सिंह बताते है कि पूर्व में देशी धान किस्मों से किसानों को औसत उपज 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा कुल आमदनी 28 हजार 9 सौ रूपये मात्र होती थी और रबी मौसम में खेत खाली पड़ा रहता था। कम अवधि के उन्नत धान प्रभेद से 23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिला। जिसका कुल बाजार मूल्य किसानों को 39 हजार 1 सौ रूपये मिला। इस तकनीक से किसानों को एक वर्ष में एक हेक्टेयर भूमि से 1 लाख 51 हजार 6 सौ रूपये की कुल आमदनी हुई। जो पूर्व वर्ष की तुलना में 224 प्रतिशत अधिक है। इस तकनीकी लाभ को देखकर रबी 2019 में गांव के किसान धान की कटाई के बाद करीब 30 हेक्टेयर भूमि में मटर की खेती करने लगे है। इस प्रत्यक्षण को प्रक्षेत्र दिवस के माध्यम से जिले के विभिन्न प्रखंडो के किसानों को परिभ्रमण कराया गया। इसके उपरांत रबी 2019 में जिले के किसानों ने करीब 300 हेक्टेयर भूमि में उपलब्ध नमी का उपयोग कर मटर की खेती की।

केवीके प्रभारी ने बताया कि इस कार्यक्रम को आईसीएआर की जलवायु समुत्थानशील कृषि पर राष्ट्रीय पहल (निकरा) परियोजना को चलाया गया। इसके तहत जिले में वर्षा में असमानता, अतिवृष्टि या अनावृष्टि, बाढ़, सुखाड़, परिवर्तनशील जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाओं के आधार पर जलवायु अनुरूप तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिले में निकरा चयनित गांवों में इन तकनीकों के उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले हैं।

पेड़ बचाने के लिए गडकरी ने बदल दिया हाइवे का नक्शा

एजेंसियां

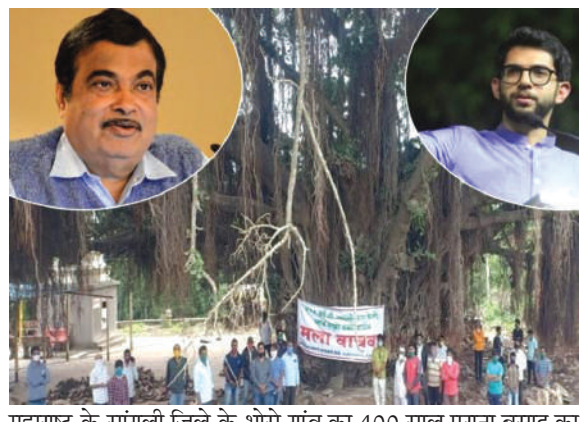

महाराष्ट्र के सांगली जिले के भोसे गांव का 400 साल पुराना बरगद का पेड़ आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सुर्खियों में है. निर्माणाधीन हाइवे का सर्विस रोड उसके पास से गुजरता है. इसलिए यह पेड़ काटकर रोड बनाई जा रही थी. मगर पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया.ि विरोध बढ़ता देख पेड़ के बारे में जब राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे को अवगत कराया गया, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात की और इस पेड़ को बचाने की मांग की थी.

आदित्य ठाकरे ने नितिन गडकरी को दी इसकी सूचनापेड़ बचाने के लिए हाइवे के नक्शे में किया बदलाव

विरोध बढ़ता देख पेड़ के बारे में जब राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे को अवगत कराया गया, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात की और इस पेड़ को बचाने की मांग की. आदित्य ठाकरे से बात करने के बाद नितिन गडकरी ने इस पेड़ को बचाने के लिए हाइवे के नक्शे में ही बदलाव करके ये प्रोजेक्ट पूरा करने का आदेश दिया है।

पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं ने भी गडकरी से पुराने पेड़ को बचाने की गुजारिश की थी। निर्माणाधीन रत्नागिरी- नागपुर हाइवे नंबर 166 सांगली जिले के भोसे गांव के पास से गुजर रहा है. सांगली के पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं ने पेड़ काटने का विरोध किया था. सोशल मीडिया, न्यूज मीडिया में यह विरोध इतना फैल गया कि राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने इसमें दखल दिया। अंततः नितिन गडकरी ने अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करके इस हाइवे के आरेखन में तब्दीली करके बरगद के इस 400 साल पुराने पेड़ को बचाने को कहा है और आखिरकार यह पेड़ बच गया है।

किसान ही बनेंगे बीज बैंक के मालिक

आत्मनिर्भर भारत योजना में दिया जाएगा लाइसेंस

एजेंसियां

देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री की घोषणा फलीभूत हो रही है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग ने बीज बैंक योजना को बड़े पैमाने पर शुरू करने का एलान किया है। इसके तहत अब देशभर में जिलेवार बीज बैंक बनेंगे। इसके लिए किसानों को ही बीज बैंक का लाइसेंस दिया जाएगा। इससे किसान बीज के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस योजना में देश के साढ़े छह सौ जिलों में बीज बैंक खोले जाने हैं।देश में इस समय लगभग तीस फीसदी बीज किसान स्वयं बनाता है बाकी बीजों के लिए उसे बाजार और सरकारी सस्ते बीजों की उपलब्धता पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में कई बार उसे बीज की गुणवत्ता के चलते बड़ी ही कम पैदावार या बीमार फसल जैसी दुश्वारियां भी झेलनी पड़ती हैं। ऐसे में किसानों को इस दिशा में सक्रिय करने के लिए मंत्रालय ने पूर्व के लाइसेंस नियमों में भी काफी ढील दी है। इसमें अब बीज बैंक के लाइसेंस के लिए कक्षा दस पास होना ही काफी होगा।

किसानों को स्थानीय कृषि प्रसार केंद्र पर प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। लाइसेंस के लिए अन्य योग्यताएं हैं उसके पास अपनी या बटाई अथवा पट्टेदारी में कम से कम एक एकड़ जमीन होनी चाहिए। उसे राज्य स्तर से बीज के स्तर और मानकों के लिए निबंधन और प्रमाणन करना होगा। सरकार द्वारा उन्हें एक मुश्त रकम प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। इसके अलावा भंडारण की सुविधा के लिए प्रशिक्षण के साथ उपलब्ध संसाधनों पर सब्सिडी भी दी जाएगी।बीज बैंक का लाइसेंस लेने वाले किसान को उसके बीज का बाजार दिलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। बीज का मूल्य भी पहले से ही तय किया जाएगा। इसके लिए फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर 20 फीसदी राशि को जोड़कर प्रसंस्करण बीज के आधार पर क्रय मूल्य का निर्धारण राज्य बीज निगम करेगा। इसके लिए बीज निगम पहले प्रयास में बीज उत्पादक किसानों के खलिहानों से बीजों का संग्रहण करेगा।

नए बीज उत्पादक किसानों को बीज उत्पादन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधन एवं केंद्रीय प्रभारी द्वारा आधार बीज मूल्य का भुगतान लेकर उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिला स्तर पर बीज बैंक हो जाने से किसान को अच्छे और सस्ते बीज मिलने की राह तो आसान होगी ही साथ ही किसान भी उच्च गुणवत्ता की फसल को उपजाने के लिए प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि उन्हें इस प्रक्रिया के चलते महंगे बीजों से निजात और उत्पादक की विश्वसनीयता का लाभ मिल सकेगा।

काली नाड़ी, कृष्णा और हिंडन नदियों में छोड़ रहे हैं गंदा पानी

एजेंसियां

एस.वी.एस राठौड़ की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट एनजीटी के समक्ष सौंप दी है मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है जहां उद्योगों से निकलने वाले गंदे पानी की नदियों में बहाया जा रहा थो रिपोर्ट के अनुसार इससे काली नाड़ी, कृष्णा और हिंडन नदी का जल दूषित हो रहा है साथ ही भूजल पर भी असर पड़ रहा है जिसके कारण वहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है

कोर्ट द्वारा गठित समिति ने 11 फरवरी, 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जिसके अनुसार मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर जिलों में उधोगों से निकले गंदे पानी और सीवेज से वहां का जल प्रदूषित हो रहा है इसके साथ ही इन इलाकों में हैंड पंप से जो पानी प्रयोग किया जा रहा है वो दूषित हो चुका है जिसका अभी भी उपयोग हो रहा है .इन प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारियों द्वारा साफ़ पानी की आपूर्ति का कोई उपाय नहीं किया गया है साथ ही गंदे पानी के कारण बीमार पड़े लोगों की पहचान और पीड़ितों को मुआवजा देने का कोई प्रयास किया है। रिपोर्ट में जानकारी दी है कि एनजीटी और समिति के बार-बार निर्देश देने के बावजूद उत्तर प्रदेश जल निगम ने अब तक 148 प्रभावित गांवों में पाइप वाटर नहीं पहुंचाया है अब तक केवल 45 गांवों में पाइप वाटर देने की व्यवस्था की गई है जबकि जुलाई 2019 में यह आंकड़ा 41 गांवों का था।

पिछले एक साल में केवल 4 गांवों तक पाइप के जरिए पानी पहुंचा है। वहीं पिछले एक साल में प्रस्तावित तीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के निर्माण में कोई प्रगति नहीं हुई है।

फोटो न्यूज

पिठौरिया रांची के रितेश दीपक ने मार्च में लॉकडाउन के शुरूआत में पपीते का पौधा लगाया जो अब पेड़ बन गया

ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से करीब 3 बिलियन जानवर खत्म हुए

एजेंसियां

अनुमान है कि 143 मिलियन स्तनधारी, 180 मिलियन पक्षी, 51 मिलियन मेंढक और 2.5 बिलियन सरीसृप आग से प्रभावित हुए

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले गैर लाभकारी संगठन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) के अध्ययन में पता चला कि 2019-20 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से करीब 3 बिलियन जानवर मर गए या विस्थापित हो गए।

एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि आग से 143 मिलियन स्तनधारी, 180 मिलियन पक्षी, 51 मिलियन मेंढक और 2.5 बिलियन सरीसृप प्रभावित हुए।

यह रिपोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल, चाल्स स्टर्ट यूनिवर्सिटी और वर्ल्डलाइफ ऑस्ट्रेलिया के 10 वैज्ञानिकों के काम के आधार पर तैयार की गई है।

अध्ययन में जितने जानवरों के मरने का अनुमान लगाया गया है, वह पूर्व के अनुमान से बहुत अधिक है। पहले कहा गया था कि आग से एक बिलियन जानवर मरे हैं।

नए अनुमान में पहले से विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन किया गया है। करीब 11.46 मिलियन हेक्टेयर को क्षेत्र को अध्ययन में शामिल किया गया है। यह क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम के बराबर है। इसमें 8.5 मिलियन वन भूमि भी शामिल है। अध्ययन में शामिल सबसे अधिक वन भूमि दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम की है। इसके अलावा 1,20,000 हेक्टेयर वन भूमि उत्तर के वर्षावन की है।

गार्जियन ने डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव डेरमोट ओ गोरमन के हवाले से बताया है कि दुनियाभर में शायद ही ऐसी कोई घटना हुई हो जहां इतनी बड़ी संख्या में पशु मरे या विस्थापित हुए हों। उन्होंने इस त्रासदी को आधुनिक इतिहास की सबसे भयानक वन्यजीव आपदा कहा है।

अध्ययन में शामिल यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के ईकोलॉजी प्रोफेसर क्रिस डिकमैन ने आग से हुए नुकसान की तुलना धरती पर मौजूद मनुष्यों की आधी आबादी से की है। उनका कहना है कि तीन हजार मिलियन वर्टब्रेट्स (कशेरुकी जीव) की क्षति बहुत बड़ी है। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसे समझना भी आसान नहीं है।

ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक 1980 के दशक से ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ने के खतरे से अवगत करा रहे थे। उन्होंने पहले ही जंगलों में आग लगने की घटनाओं की आशंका जाहिर कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया ने अब इन घटनाओं की जांच के लिए रॉयल कमिशन का गठन किया है, जिसकी रिपोर्ट अक्टूबर तक आने की उम्मीद है।

पंजाब ने बनाई पुआल से बिजली बनाने की योजना

सुसान चाको /ललित मौर्य

हर साल फसल कटने के बाद पंजाब और हरियाणा में किसान पराली जलाते हैं। इससे बहुत ही ज्यादा मात्रा में धुंआ औश्र प्रदूषण होता है। इसका असर दिल्ली के आकाश पर भी होता है। इस प्रदूषण पर राजनीति भी खूब होती है। सारे दल एक दूसरे पर इस-ाका ठिकरा फोड़ते हैं, पर निदान कोई नहीं सूझाता।

हाल में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने पुआल से बिजली बनाने के सन्दर्भ में अपनी रिपोर्ट एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत कर दी है मामला पंजाब के बठिंडा जिले का है, जहां थर्मल पावर प्लांट को पुआल से चलने की योजना है जिससे पुआल को जलाने से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के सेवानिवृत्त इंजीनियर दर्शन सिंह ने इस परियोजना पर एनजीटी के समक्ष आवेदन किया था। अदालत ने दर्शन सिंह के उस आवेदन को 2019 के ओऐ नंबर 1039 में दर्शन सिंह बनाम पंजाब और अन्य राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया थो जिसपर कोर्ट ने 27 जनवरी को एक आदेश पारित कियो जिसमें पीपीसीबी और पीएसपीसीएल और पंजाब एनर्जी एजेंसी को निर्देश दिया गया कि इस मामले पर अपनी राय पेश करे। इस मामले में दर्शन सिंह के प्रस्ताव की जांच करने के लिए कोर्ट ने एक समिति गठित की थी। प्रस्ताव के अनुसार भटिंडा में थर्मल पॉवर प्लांट को कोयले की जगह पुआल से चलाने की योजना है इसके संबंध में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया है:

- **नए बायोमास संयंत्र की स्थापना की तुलना में थर्मल पावर प्लांट में परिवर्तन करना सस्ता है साथ ही इससे बिजली उत्पादन की लागत में भी कमी आएगी, जिससे उपभोक्ताओं पर कम बोझ पड़ेगा।**

- **विशेषज्ञों ने इस संयंत्र को विशेष रूप से पुआल पर चलाने के लिए पंजाब राज्य विद्युत निगम (पीएसपीसीएल) को एक रिपोर्ट सौंपी है।**

इस मामले पर पीएसपीसीएल ने 21 नवंबर 2018 को एक बैठक की थी जिसमें उसने 120 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट में से 60 मेगावाट को परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी थी। नवंबर 2018 से यह प्रस्ताव राज्य सरकार के पास है जिसपर कोई फैसला नहीं लिया गया है।

लॉकडाउन में घर लौटे मजदूरों के कारण देश में धान का रकबा बढ़ा

एजेंसियां :कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के खरीफ के मौजूदा बुलेटिन की मानें तो कवरेज क्षेत्र यानी रकबा पिछले वर्ष के 23 मिलियन हेक्टेयर के मुकाबले अब 43.3 मिलियन हेक्टेयर यानी लगभग दोगुना हो गया है। धान का कवरेज भी पिछले साल के 4.9 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर इस साल 6.8 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां बड़ी संख्या में लोग लौटें हैं, वहां यह कवरेज काफी बढ़ा है। आंकड़े यह नहीं बताते कि खेती से लोगों का जुड़ाव स्थायी है लेकिन यह संकेत जरूर देते हैं कि कुछ कारणों ने लोगों ने खेती का रकबा बढ़ा दिया है। हो सकता है कि यह अच्छी बारिश की वजह से हुआ हो। यह भी संभव है कि खेती के लिए मजदूरों की उपलब्धता को देखते हुए रकबा बढ़ा हो।

किसानों से बातचीत में एक अन्य तथ्य भी सामने आया है। बहुत से लोग कह सकते हैं कि यह सिर्फ खतरे से बचने की प्रवृति हो सकती है। लेकिन यह तथ्य है कि किसान परिवार के जो लोग अतिरिक्त आय के लिए बाहर गए थे, वे लौट आए हैं। कृषि में वे अतिरिक्त मजदूर लगा रहे हैं। लेकिन क्या इससे फिर से कृषि से जुड़ने की प्रवृत्ति बढ़ेगी? यह काफी हद तक अतिरिक्त संसाधनों को खेती में लगाने के नतीजों पर निर्भर करेगा। इसका अर्थ है कि अगर उन्हें अच्छा मेहनताना मिलेगा तो वे इससे जुड़े रहेंगे।

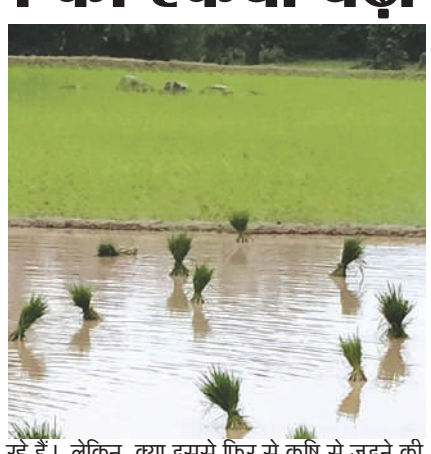

मिशन आर्गेनिक : जैविक खेती से बदल रहा लद्दाख के किसानों का जीवन

एजेंसियां : केमिकल खेती के चलते तेजी से बंजर हो रही जमीन को बचाने के लिए जैविक खेती का अभियान शुरू किया गया ।यूं तो पूरे देश में किसानों के हालात बदल रहे हैं लेकिन लद्दाख में इसका सबसे अधिक असर और चलन देखने को मिल रहा है।

किसानों ने भी मिशन आर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव (मोदी) के तहत 66 गांवों में जैविक खेती की मदद से न केवल आय में इजाफा कर रहे हैं, बल्कि खेतों और जलवायु को भी रसायन के प्रयोग के चलते होने वाले नुकसान से बचा रहे हैं। इसके चलते किसान एक ही खेत में फूल, तरबूज, गाजर, गोभी ब्रोकली और शिमला मिर्च का उपजा रहे हैं। जबकि पहले लद्दाख में छह माह जब मौसम ठीक रहता है, अमूमन किसान एक फसल की उपज करते थे, लेकिन अब वह एक से ज्यादा फसलों के उत्पादन में नवीन और उन्नत जैविक तकनीकों के माध्यम से सक्षम हो गए हैं।

हाल ही में सिक्किम की तर्ज पर पूरे लद्दाख को जैविक खेती के लिए प्रेरित करने के लिए तीन चरणों में बांट कर विधिवत ढंग से मोदी योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत 2025 तक पूरे लद्दाख को उर्वरक खेती से मुक्त करना है। इसके कृषि विकास विभाग द्वारा किसानों को सस्ते बीज जैविक खाद बनाने के परीक्षण के अलावा ग्रीन हाउस भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं ।जिसकी मदद से किसान एक ही खेत में कई तरह की फसलों को उपजा पा रहे हैं।

इस योजना से एक अनुमान मुताबिक लद्दाख के 40 फीसदी किसानों को फायदा होगा। 241 गांवों के किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यहां किसान साल भर में होने वाली एक फसल के बजाए तीन से चार फसलें उगाने में सक्षम हो जाएंगे।

2019 में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ की स्थायी समिति ने संरक्षित क्षेत्रों में दी कई परियोजनाओं को मंजूरी और

481.56 हेक्टेयर वनभूमि परियोजनाओं को दे दी

इशान कुकरेती

नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ (एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति द्वारा साल 2019 में संरक्षित क्षेत्रों की 481.56 हेक्टेयर वनभूमि विभिन्न परियोजनाओं को दे दी गई। संरक्षित वनभूमि में वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यानों की भूमि भी शामिल है।

यह जानकारी एनेलिसिस ऑफ वाइल्डलाइफ क्लीयरेंसेस इन इंडिया 2019 (जनवरी से दिसंबर) पेपर में 6 अगस्त 2020 को प्रकाशित हुई है। इसका विश्लेषण दिल्ली स्थित लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट द्वारा किया गया है। जिन 68 परियोजनाओं के लिए वनभूमि दी गई उनमें सिंचाई, रेलवे, खनन आदि शामिल हैं। स्थायी समिति ने 2019 में कुल 156 परियोजनाओं पर विचार किया जिनमें से 68 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। इनमें रेलवे की तीन परियोजनाएं शामिल हैं जिनमें 53 प्रतिशत भूमि वनभूमि इस्तेमाल होगी।

एनबीडब्ल्यूएल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत गठित वैधानिक संगठन है। यह केंद्र सरकार को वन्यजीवों के संरक्षण के लिए नीतियां बनाने और सलाह देने का काम करता है। पेपर में कहा गया है, ''वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्र की कुल 481.56 हेक्टेयर भूमि परियोजनाओं हेतु दी गई और केवल एक प्रस्ताव खारिज किया गया है।''

इस वनभूमि में 87 प्रतिशत (418.70 हेक्टेयर) लीनियर प्रोजेक्ट, 7 प्रतिशत (35.83 हेक्टेयर) सिंचाई, 4 प्रतिशत (17.5 हेक्टेयर) आधारभूत सुविधाओं और शेष दो प्रतिशत (9.52 हेक्टेयर) खनन परियोजनाओं के लिए है। लीनियर प्रोजेक्ट में रेलवे, सड़क, ट्रांसमिशन लाइन, पुल, सुरंग और पाइपलाइन से जुड़ी परियोजनाओं शामिल हैं।

वनभूमि का बड़ा हिस्सा रेलवे की तीन परियोजनाओं मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन), कैसल रॉक- कुलेम-मडगांव रेलवे डबलिंग प्रोजेक्ट (गोवा) और सकरी-बिरौल-कुशेष्वर स्थान (बिहार) परियोजनाओं के खाते में गया है। विश्लेषण के मुख्य लेखकों में शामिल आरके सिंह ने कहा है कि संरक्षित क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रभाव का कोई अध्ययन किए बिना कई परियोजनाओं की सिफारिश की जा रही है। कई परियोजनाएं पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के दायरे में भी नहीं आती। केवल प्रभागीय वन अधिकारी की टिप्पणियों पर विचार किया जाता है। उन्होंने कहा कि कई परियोजनाएं ऐसी हैं जिन्हें कहीं और भी किया जा सकता था।

लुभाएंगी आम की दीपशिखा और मनोहारी किस्में

अमित शर्मा

अपेक्षाकृत कम मिठास और चटख लाल रंग के कारण पूसा दीपशिखा आम को अमेरिकी बाजार में मिल सकती है बड़ी कामयाबी

वर्तमान में भारत फलों-सब्जियों के निर्यात में चीन के बाद दूसरे नंबर पर, वर्तमान में फलों का उत्पादन 9.797 करोड़ टन और सब्जियों का उत्पादन 18.317 करोड़ टन प्रति वर्ष है ।

फलों का राजा आम अपनी मिठास के कारण पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बजा रहा है। इसका सीधा लाभ हमारे देश के आम उत्पादक किसानों और व्यापारियों को हुआ है। यूरोपीय और अमेरिकी समाज के लोग अपेक्षाकृत कम मिठास के फल खाना ज्यादा पसंद करते हैं। यही कारण है कि उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए पूसा के वैज्ञानिकों ने दो ऐसे विशेष आम विकसित किए हैं जो अन्य आम फलों की तुलना में कम मीठे हैं, लेकिन अपने स्वाद और स्वास्थ्यवर्धक गुणों के कारण इनकी खूब मांग रह सकती है। कम मीठा होने के कारण शुगर पीड़ित लोग भी इसे खा सकते हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (पूसा), नई दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संजय सिंह ने अमर उजाला को बताया कि 'पूसा दीपशिखा (हाईब्रिड 11-2)' आम्रपाली और सेंसशन के संकरण से प्राप्त संकर किस्म है। इसके पेड़ नियमित फल देने वाले और अर्ध-बौने आकार के होते हैं।

इस प्रजाति के पेड़ों से प्राप्त फल अधिकांशतया सामान आकार के, लंबे आकार के, आकर्षक, चमकदार, लाल छिलके और नारंगी-पीले गूदे वाले होते हैं, जो अमेरिकी-यूरोपीय समुदाय में बहुत पसंद किए जाते हैं। इनके पेड़ों को मध्यम सघन बागवानी 66 मीटर पर लगाना ज्यादा लाभदायक है। प्रति हेक्टेयर के आधार पर लगभग दस साल पुराना पेड़ 50.33 किलोग्राम फल देता है। इस किस्म की प्रति हेक्टयर अनुमानित उपज 14.3 टन है।

पूसा दीपशिखा (हाइब्रिड 11-2) के फल मध्यम मिठास (18.67 डिग्री ब्रिक्स) वाले, 70 फीसदी गूदे वाले, एस्कोर्बिक एसिड (35.34 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम गूदा) और बीटा कैरोटीन (9.48 मिलीग्राम) पाया गया है। इन फलों की भंडारण आयु कमरे के सामान्य तापमान पर भी 7-8 दिनों की होती है। इससे व्यापारियों को बिना फल खराब हुए इसे बेचने के लिए लंबा समय मिलता है, जो व्यापारिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होता है।

पूसा मनोहारी आम की संकर किस्म आम्रपाली और लाल सुंदरी आमों की विशेषताओं के संकरण से बनाया गया है। आम के बौर लगने के समय आमों में लगने वाला गुच्छा रोग आम की फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन यह नई किस्म इस रोग के प्रति सहनशील (10-15 फीसदी) पाई गई है। यह भी मध्यम सघन बागवानी वाली आम की फसल है, जो मध्यम आकार (223 ग्राम औसतन) के फल देती है। लगभग दस साल पुराना पेड़ औसतन 58 किलोग्राम फल देता है। इससे अनुमानित तौर पर प्रति हेक्टेयर 16.1 टन की फसल प्राप्त की जा सकती है।

ये फल भी हल्के लाल रंग की आभा लिए हरे-पीले छिलके वाले होते हैं। लेकिन इसका गूदा रेशा रहित नारंगी पीला होता है, जो देखने में काफी अच्छा लगता है। इन फलों की मिठास क्षमता (20.38 डिग्री ब्रिक्स), अम्लता (0.27 प्रतिशत), एस्कोर्बिक अम्ल (39.78 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम गूदा), बीटा कैरोटीन (9.73 मिलीग्राम प्रति एक किलोग्राम गूदा) होता है।

फलों के बाजार में भारत की स्थिति

केंद्र सरकार की नीतियों के कारण बागवानी क्षेत्र में भारत ने 2013-14 के बाद से बहुत अच्छी प्रगति की है। 2018-19 में 2.543 करोड़ हेक्टेयर भूक्षेत्र में बागवानी की खेती हुई है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस वर्ष 31.074 करोड़ टन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया गया।

वर्तमान समय में भारत फलों-सब्जियों के निर्यात के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। वर्तमान में देश फलों का उत्पादन 9.797 करोड़ टन और सब्जियों का उत्पादन 18.317 करोड़ टन प्रति वर्ष है। भारतीय कृषि वैज्ञानिकों द्वारा पैदा की गई नई-नई फलों-सब्जियों के कारण यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सका है।

E ZONE CARE

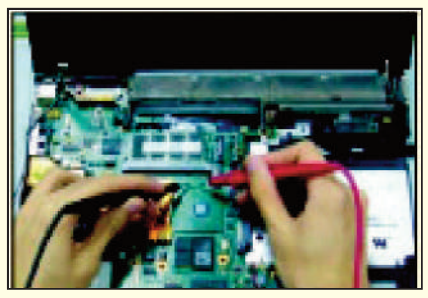

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

- **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।